

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 306]

नवा रायपुर, मंगलवार, दिनांक 9 जून 2026 — ज्येष्ठ 19, शक 1948

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 9 जून 2026

अधिसूचना

File No. PLGMJ-2601/1319/2025-GAD-1.— यतः, पहचान साबित करने के लिए आधार नंबर का उपयोग करने से लोगों को सुविधाजनक और निर्बाध रूप से सहायिकी (सब्सिडी), लाभ और सेवाएं मिलती हैं, पहचान स्थापित करने के लिए कई दस्तावेजों की ज़रूरत खत्म हो जाती है, प्रक्रिया आसान हो जाती है और पारदर्शिता एवं दक्षता को बढ़ावा मिलता है;

और यतः, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा (जो इसमें इसके पश्चात् उक्त विभाग के रूप में निर्दिष्ट है) छत्तीसगढ़ शासन में (जो इसमें इसके पश्चात् राज्य सरकार के रूप में निर्दिष्ट है) मंत्री परिषद् सदस्य स्वेच्छानुदान नियम, 2019 (जो इसमें इसके पश्चात् उक्त योजना के रूप में निर्दिष्ट है) का संचालन किया जा रहा है;

और यतः, विशिष्ट व्यक्ति एवं संस्थाओं (जो इसमें इसके पश्चात् लाभार्थी के रूप में निर्दिष्ट है) को खेल, शिक्षा, कला, विज्ञान, ईमानदारी एवं बहादुरी हेतु पुरस्कार के रूप में अनुदान, चिकित्सा उपचार हेतु अनुदान, निर्धन या दिव्यांग व्यक्तियों हेतु अनुदान, कन्या विवाह हेतु अनुदान, स्वरोजगार हेतु अनुदान, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को अनुदान, अनाथों को अनुदान (यदि नाबालिग हो तो पालक के नाम पर), बच्चों के शिक्षण हेतु अनुदान (पालक/शिक्षण संस्थान के नाम पर), (जो इसमें इसके पश्चात् उक्त लाभ के रूप में निर्दिष्ट है) दिया जा रहा है;

संस्थाओं के मामले में, ऐसे सभी सार्वजनिक प्रयोजन शामिल होंगे जो लोकहित स्वरूप के हों;

और यतः, उक्त योजना पर होने वाला व्यय, राज्य शासन की समेकित निधि क्रमांक 01-2013-105-9064 #14-008 विवेकाधीन अनुदान मद के अंतर्गत वहन किया जाता है;

और यतः, उक्त सामान्य प्रशासन विभाग इच्छुक है कि सरकार, उक्त लाभ प्राप्त करने के लिए शर्त के रूप में लाभार्थी की पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से, ऐसे लाभार्थी का अधिप्रमाणन करवाए या आधार नंबर होने का सबूत दे या जिस व्यक्ति को कोई आधार नंबर नहीं दिया गया है, वह नामांकन के लिए आवेदन करे;

अतएव, आधार (वित्तीय एवं अन्य सहायिकियों (सब्सिडी), प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (जो इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 7 के प्रावधानों के अनुसरण में, छत्तीसगढ़ सरकार, एतद्वारा, आधार संख्या के प्रमाण के लिए निम्नलिखित निर्देश अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

1. (1) उक्त योजना के तहत उक्त प्रसुविधाओं का उपयोग करने के इच्छुक व्यक्ति को अधिप्रमाणन करवाना होगा या आधार नंबर होने का सबूत देना होगा।
(2) ऐसे व्यक्ति की दशा में, जिसे आधार नंबर नहीं दिया गया है, तो उसे नामांकन के लिए आवेदन करना होगा;

परंतु यदि वह व्यक्ति बालक/बालिका है, तो ऐसा आवेदन सिर्फ उसके माता-पिता या विधिक संरक्षक की सहमति से ही किया जाएगा।

- (3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियमन, 2016 के विनियम 12 के प्रावधानों के अनुसार, उक्त सामान्य प्रशासन विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे लाभार्थियों जिनका अभी तक नामांकन नहीं हुआ है, उनका नामांकन किया जाए या वे उचित उपायों से अपने आधार संबंधी ब्यौरों को अद्यतन करें, जिसमें रजिस्ट्रार के साथ समन्वय करना और सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन केन्द्र स्थापित करना या रजिस्ट्रार द्वारा स्वयं नामांकन सुविधाएं प्रदान करवाना है:

परंतु जब तक ऐसे लाभार्थी को आधार नंबर नहीं मिल जाता, तब तक वह उक्त लाभ उठाने के लिए अपनी पहचान साबित करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज पेश कर सकता है, जिनके लिए वह हकदार है और जो पेश करने के समय वैध हैं या यदि उक्त सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा ऐसे पहचान के लिए प्रदान किया गया या अधिकृत सॉफ्टवेयर, ऐसे दस्तावेज की सामग्री को साबित करने वाली जानकारी को उन प्राधिकरण के डेटाबेस से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने में सक्षम है, जो उन्हें तैयार करने या बनाए रखने का काम करती हैं, तो वह ऐसा करने के लिए अपनी सहमति दे सकता है, अर्थात्:-

18 वर्ष से कम आयु के बालक/बालिका, जिसे आधार नंबर नहीं मिला है:

- (अ) नामांकन केन्द्र पर ऑपरेटर द्वारा प्रदान की गई, लाभार्थी के नामांकन प्रक्रिया से गुजरने की अभिस्वीकृति, जिसमें नामांकन ID (EID) हो; और
- (ब) यह साबित करने के लिए कि लाभार्थी 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा है, नीचे दिए गए दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात्:-

(एक) जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 (क्र. 18 सन् 1969) के तहत दिया गया जन्म प्रमाण पत्र, जैसा कि लाभार्थी के जन्म के संबंध में जन्म रजिस्टर में की गई प्रविष्टि से लिया गया है;

(दो) भारतीय पासपोर्ट;

(तीन) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन या 10वीं कक्षा या हायर सेकेंडरी या 12वीं कक्षा का प्रमाणपत्र या अंकसूची;

(चार) देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चे या "विधि से संघर्षरत" बालक/बालिका के मामले में, जो किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत संबंधित राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के तहत पंजीकृत बाल देखभाल संस्थान में रहते हैं, उस संस्थान के प्रभारी व्यक्ति, अधीक्षक (सुपरिटेण्डेंट), बाल कल्याण अधिकारी या परिबीक्षा (प्रोबेशन) अधिकारी द्वारा जारी किया गया जन्म तिथि बताने वाला प्रमाण पत्र; या

(पाँच) किसी विदेशी नागरिक के संबंध में,-

(क) यदि वह भारत का प्रवासी नागरिक कार्डधारक है, तो भारत का प्रवासी नागरिक कार्ड;

(ख) यदि वह तिब्बती शरणार्थी है, तो विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र;

(ग) यदि वह नेपाल या भूटान का नागरिक है, तो नेपाल या भूटान का पासपोर्ट;

(घ) यदि वह भारत का प्रवासी नागरिक कार्डधारक, तिब्बती शरणार्थी या नेपाल या भूटान का नागरिक नहीं है, तो उसके पास विदेशी पासपोर्ट के साथ भारतीय वीजा या वर्तमान में वैध या समाप्त हो चुके विदेशी पासपोर्ट के साथ भारत का दीर्घकालिक वीजा होना चाहिए; या

(स) लाभार्थी की तस्वीर वाले निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज, जिससे माता-पिता या विधिक संरक्षक के साथ उसका रिश्ता साबित हो, जैसे:-

(एक) राशन कार्ड;

- (दो) राज्य सरकार के एक राजपत्रित अधिकारी, जो कार्यकारी मजिस्ट्रेट या तहसीलदार के पद से निम्न रैंक का राजस्व अधिकारी न हो, द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र या अधिवास प्रमाण पत्र;
- (तीन) किसी सरकारी संस्था या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा सेवानिवृत्त या सेवारत सरकारी कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य को जारी किया गया मेडिकल या बीमा पहचान पत्र;
- (चार) भारतीय पासपोर्ट;
- (पाँच) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिक या 10वीं कक्षा या उच्चतर माध्यमिक या 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र या अंकसूची;
- (छः) देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बालक/बालिका या विधि से संघर्षरत बालक/बालिका के संबंध में, जो किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के तहत संबंधित राज्य सरकार के साथ पंजीकृत बाल देखभाल संस्थान में रहता है, ऐसे संस्थान के प्रभारी व्यक्ति, अधीक्षक, बाल कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी द्वारा जारी जन्म तिथि निर्दिष्ट करने वाला प्रमाण पत्र; या
- (सात) किसी विदेशी नागरिक के संबंध में,-
- (क) यदि वह भारत का प्रवासी नागरिक कार्डधारक है, तो भारत का प्रवासी नागरिक कार्ड;
- (ख) यदि वह तिब्बती शरणार्थी है, तो विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र;
- (ग) यदि वह नेपाल या भूटान का नागरिक है, तो नेपाल या भूटान का पासपोर्ट;
- (घ) यदि वह भारत का प्रवासी नागरिक कार्डधारक, तिब्बती शरणार्थी या नेपाल या भूटान का नागरिक नहीं है, तो उसके पास विदेशी पासपोर्ट के साथ भारतीय वीजा या वर्तमान में वैध या समाप्त हो चुके विदेशी पासपोर्ट के साथ भारत का दीर्घकालिक वीजा होना चाहिए; या
- (आठ) जिस लाभार्थी का कोई विधिक संरक्षक है, उसके संबंध में, गोद लेने का आदेश या विधिक संरक्षक होने का सबूत देने वाला कोई अन्य दस्तावेज़, जो गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट, 1890, जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन) एक्ट, 2015, नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज एक्ट, 1999 या राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, 2016 और उक्त अधिनियमों के तहत बनाए गए लागू नियमों और विनियमों के तहत किसी न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो; या
- (नौ) कोई अन्य दस्तावेज़, जैसा कि उक्त ऊर्जा विभाग निर्दिष्ट कर सकता है।

जिन लाभार्थियों की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है और जिन्हें आधार नंबर नहीं मिला है, उनके लिए:

- (अ) नामांकन केन्द्र पर ऑपरेटर द्वारा प्रदान की गई, लाभार्थी के नामांकन प्रक्रिया से गुज़रने की अभिस्वीकृति, जिसमें नामांकन ID (EID) हो; और
- (ब) लाभार्थी की फोटो वाले नीचे दिए गए दस्तावेजों में से कोई एक, जैसे:-
- (एक) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया मतदाता फोटो पहचान पत्र;
- (दो) राशन कार्ड;
- (तीन) राज्य सरकार के एक राजपत्रित अधिकारी, जो कार्यकारी मजिस्ट्रेट या तहसीलदार के पद से निम्न रैंक का राजस्व अधिकारी न हो, द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र या अधिवास प्रमाण पत्र;
- (चार) किसी सरकारी संस्था या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा सेवानिवृत्त या सेवारत सरकारी कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य को जारी किया गया मेडिकल या बीमा पहचान पत्र;

- (पाँच) भारतीय पासपोर्ट;
- (छः) किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन या 10वीं कक्षा या उच्चतर माध्यमिक या 12वीं कक्षा का प्रमाणपत्र या अंकों का विवरण;
- (सात) किसी सरकारी संस्था या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा सेवारत या सेवानिवृत्त लोक सेवक को जारी किया गया पहचान पत्र या अन्य पहचान दस्तावेज;
- (आठ) दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के अंतर्गत अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र, या भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जारी विशिष्ट दिव्यांगता पहचान (यूडीआईडी) पत्र;
- (नौ) भारत में जारी चालन अनुज्ञप्ति (डाइविंग लाइसेंस);
- (दस) देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक/बालिका या विधि से संघर्षरत बालकों के संबंध में, जिन्हें किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत उसके द्वारा बनाए गए नियमों के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकार के साथ पंजीकृत बाल देखभाल संस्थान में रखा जाता है, ऐसे संस्थान के प्रभारी व्यक्ति, अधीक्षक, बाल कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी द्वारा जारी उसकी जन्मतिथि निर्दिष्ट करने वाला प्रमाणपत्र; या
- (ग्यारह) किसी विदेशी नागरिक के संबंध में-
- (क) यदि वह भारत का प्रवासी नागरिक कार्डधारक है, तो भारत का प्रवासी नागरिक कार्ड;
- (ख) यदि वह तिब्बती शरणार्थी है, तो विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र;
- (ग) यदि वह नेपाल या भूटान का नागरिक है, तो नेपाल या भूटान का पासपोर्ट;
- (घ) यदि वह भारत का प्रवासी नागरिक कार्डधारक, तिब्बती शरणार्थी या नेपाल या भूटान का नागरिक नहीं है, तो उसके पास विदेशी पासपोर्ट के साथ भारतीय वीज़ा या वर्तमान में वैध या समाप्त हो चुके विदेशी पासपोर्ट के साथ भारत का दीर्घकालिक वीज़ा होना चाहिए; या
- (बारह) जिस लाभार्थी का कोई विधिक संरक्षक है, उसके संबंध में, गोद लेने का आदेश या विधिक संरक्षक होने का सबूत देने वाला कोई अन्य दस्तावेज़, जो गार्डियंस एंड वाडर्स एक्ट, 1890 (1890 का 8), जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन) एक्ट, 2015, (2016 का 2) नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज एक्ट, 1999 (1999 का 44) या राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, 2016 (2016 का 49) और उक्त अधिनियमों के तहत बनाए गए लागू नियमों और विनियमों के तहत किसी कोर्ट या सक्षम प्राधिकारण द्वारा जारी किया गया हो; या
- (तेरह) कोई अन्य दस्तावेज़, जैसा कि उक्त सामान्य प्रशासन विभाग निर्दिष्ट कर सकता है।
- (4) इस संबंध में उक्त सामान्य प्रशासन विभाग/सीएसपीडीसीएल द्वारा नामित अधिकारी, खण्ड (3) के तहत पेश किए गए दस्तावेज़ों या उनकी सामग्री को साबित करने वाली जानकारी के संबंध में जाँच करेंगे, -
- (अ) myAadhaar पोर्टल (<https://myaadhaar.uidai.gov.in/portal>) पर EID जमा करके नामांकन निवेदन (रिक्वेस्ट) की प्रास्थिति की जाँच करें, ताकि इसकी पुष्टि हो सके कि EID वैध है और नामांकन निवेदन (रिक्वेस्ट) अस्वीकृत नहीं हुआ है; और
- (ब) दूसरे दस्तावेज और इस प्रयोजन के लिए, किसी भी सरकारी संस्था या प्राधिकरण की मदद ले सकते हैं और उनके साथ जानकारी बांट सकते हैं, जो ऐसे दस्तावेज़ों में मौजूद जानकारी को तैयार करने या बनाए रखने का काम करती है।
2. लाभार्थियों को उक्त लाभ आसानी से मिल सके, इसके लिए मंत्रालय, मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे ताकि लाभार्थियों को इस योजना के तहत आधार नंबर की आवश्यकता के संबंध में जानकारी हो सके।

3. जहाँ किसी लाभार्थी के आधार नंबर का प्रमाणीकरण बायोमेट्रिक-आधारित प्रमाणीकरण के किसी भी तरीके (जैसे, चेहरे की इमेज, फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन आधारित प्रमाणीकरण) से बायोमेट्रिक जानकारी की खराब गुणवत्ता (क्वालिटी) जैसे किसी भी कारण से असफल हो जाता है, तो निम्नलिखित सुधार तंत्र अपनाए जाएंगे, अर्थात्:-
 - (अ) अगर बायोमेट्रिक-आधारित प्रमाणीकरण की कोई विशेष रीति सफल नहीं होती है, तो जहाँ भी संभव और स्वीकार्य हो, बायोमेट्रिक-आधारित प्रमाणीकरण का कोई दूसरा तरीका या वन-टाइम पिन (OTP) आधारित प्रमाणीकरण दिया जाएगा;
 - (ब) ऐसे मामलों में, जहाँ बायोमेट्रिक-आधारित या OTP-आधारित प्रमाणीकरण संभव नहीं है, तो UIDAI के डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का आधार सिन्क्योर क्विक रिस्पॉन्स (QR) कोड या आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई-केवाईसी दस्तावेज पर ऑफलाइन वेरिफिकेशन करके आधार नंबर की वास्तविकता/यथार्थता स्थापित करने के बाद, बताई गई योजना के तहत लाभ इनमें से किसी भी आधार पर दिए जा सकते हैं।
 - (एक) आधार कार्ड, आधार लेटर (यानी, आधार नंबर बनने पर आधार नंबर होल्डर को जारी किया गया लेटर) या ई-आधार (यानी, UIDAI की वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकने वाली या उसके mAadhaar ऐप से एक्सेस की जा सकने वाली पासवर्ड-प्रोटेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉपी) वाला एक आधार सिन्क्योर क्विक रिस्पॉन्स (QR) कोड, जिसकी वास्तविकता/यथार्थता आधार QR स्कैनर या mAadhaar ऐप का उपयोग करके QR कोड को स्कैन करके ऑफलाइन वेरिफिकेशन से की गई हो।
 - (दो) आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई- KYC डॉक्यूमेंट (UIDAI की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकने वाला या उसके mAadhaar ऐप से एक्सेस किया जा सकने वाला), जिसकी वास्तविकता इस उद्देश्य के लिए संबंधित मंत्रालय या विभाग या योजना लागू करने वाले अभिकरण (एजेंसी) द्वारा विकसित एप्लीकेशन के माध्यम से दस्तावेज पर UIDAI के हस्ताक्षर प्रमाणपत्र सर्टिफिकेट के ऑफलाइन सत्यापन से की गई हो, UIDAI की वेबसाइट पर इस संबंध में दिए गए विवरण के अनुसार।
4. ऊपर अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी,-
 - (अ) उक्त योजना के अंतर्गत लाभ से किसी बालक/बालिका को वंचित नहीं किया जाएगा-
 - (एक) प्रमाणीकरण द्वारा अपनी पहचान स्थापित करने में या आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करने में असफल रहने की स्थिति में; या
 - (दो) नामांकन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में, जहाँ उसे आधार संख्या नहीं दी गई है; और
 - (ब) इस योजना के तहत लाभ ऐसे बालक/बालिका को उसकी पहचान का सत्यापन करके और पैराग्राफ 1 के खण्ड (3) के प्रावधान में बताई गई रीति से उसके माता-पिता या विधिक संरक्षक के साथ उसके रिश्ते को साबित करके दिया जाएगा; और
 - (स) जहाँ खण्ड (ख) के तहत लाभ दिया जाता है, वहाँ उसका एक रिकॉर्ड रखा जाएगा, उर्जा विभाग द्वारा जिसका समय-समय पर समीक्षा और अंशेक्षण किया जाएगा।
5. यह सुनिश्चित करने के लिए कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के वास्तविक हकदार लोगों को इस योजना के तहत मिलने वाले लाभ से वंचित न किया जाए, सामान्य प्रशासन विभाग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिशन, कैबिनेट सेक्रेटरीएट, भारत सरकार के ऑफिस मेमोरेण्डम D-26011/04/2017-DBT, तारीख 19 दिसंबर, 2017 में बताए गए एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म को फॉलो करेगा (जो <https://@dbtbharat-gov.in> पर उपलब्ध है)।
6. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

उक्त नियमों में शिथिलता प्रदान करते हुए मुख्यमंत्री सुसंगत योजना के अंतर्गत अनुदान स्वीकृत कर सकेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अविनाश चम्पावत, सचिव.

परिशिष्ट-एक

जन्म प्रमाणपत्र

Nava Raipur Atal Nagar, the 9th June 2026

NOTIFICATION

File No. PLGMJ-2601/1319/2025-GAD-1.— Whereas, the use of Aadhaar number to establish identity enables individuals to receive subsidies, benefits and services in a convenient and seamless manner, obviates the need for multiplicity of documents to establish identity, simplifies processes and promotes transparency and efficiency:

And whereas the General Administration Department (hereinafter referred to as the said Department) in the Government of Chhattisgarh (hereinafter referred to as the State Government) is administering Mantri Parishad Sadasy Swekchhanudan Niyam 2019 (hereinafter referred to as the said scheme):

And whereas grant is given to Specific Person (hereinafter referred to as the beneficiaries) in the form of award for sports, education, art, science, honesty and bravery, grant for medical treatment, grant to destitute or handicapped person, grant for daughter's marriage, grant for self-employment, grant to economically weak person, grant to orphan (in the name of guardian if minor), grant for education of children (in the name of guardian/educational institution) (hereinafter referred to as the said benefit).

In case of institutions, all such public purposes shall be included which are of public interest nature.

And whereas expenditure for the said scheme is incurred from the Consolidated Fund under Head No. 01-2013-105-9064 #14-008 Discretionary Grant Item of State Government:

And whereas the said General Administration Department is desirous that the Government, for the purpose of establishing identity of a beneficiary as a condition for the receipt of the said benefit, require that such beneficiary undergo authentication, or furnish proof of Aadhaar number or in the case of an individual to whom no Aadhaar number has been assigned, make an application for enrolment:

Now, therefore, in pursuance of the provisions of Section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (No. 18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Government of Chhattisgarh hereby notifies the following directions for proof of Aadhaar number, namely:—

1. (1) An individual desirous of availing of the said benefit under the said scheme shall be required to undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number.
- (2) In case such an individual has not been assigned an Aadhaar number, he shall be required to make an application for enrolment:

Provided that if that individual is a child, such application shall be made only with the consent of his parent or legal guardian.

- (3) In accordance with the provisions of regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the said General Administration Department shall ensure enrolment of such beneficiaries who are yet to be enrolled, or update their Aadhaar details through appropriate measures, including coordination with Registrars and setting up enrolment centres at convenient locations or providing enrolment facilities by becoming a Registrar itself:

Provided that till such time an Aadhaar number is assigned to such beneficiary, he may establish his identity to avail of the said benefit, by presenting the following documents to which he is entitled and which are valid at the time of presentation, or, in case the software provided or authorised by the said General Administration Department for such identification supports electronic obtaining of information evidencing the contents of such documents from the database of the authorities dealing with the preparation or maintenance thereof, by giving his consent for so obtaining, namely:—

For a child below 18 years of age to whom an Aadhaar number has not been assigned,-

- (A) The acknowledgement of the beneficiary having undergone the process of enrolment, provided by the operator at the enrolment centre, containing the Enrolment ID (EID); and
- (B) Any one of the following documents to evidence that the beneficiary is a child below 18 years of age, namely:—
 - (i) Certificate of birth given under the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (No. 18 of 1969), as extracted from the entry made in the register of births regarding the birth of the beneficiary;

- (ii) Indian passport;
 - (iii) Certificate or statement of marks of matriculation or 10th class or higher secondary or 12th class, issued by a recognised board of school education;
 - (iv) In respect of a child in need of care and protection or a child in conflict with law, who is housed by Child Care Institution registered as such with the State Government concerned under the rules made by it under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (No. 2 of 2016), certificate specifying his date of birth issued by the person-in-charge, superintendent, child welfare officer or probation officer of such institution; or
 - (v) In respect of a foreign national,—
 - (a) if he is an Overseas Citizen of India Cardholder, Overseas Citizen of India Card;
 - (b) if he is a Tibetan refugee, registration certificate issued by a Foreigners Regional Registration Office;
 - (c) if he is a national of Nepal or Bhutan, passport of Nepal or Bhutan;
 - (d) if he is other than a Overseas Citizen of India Cardholder, Tibetan refugee or a national of Nepal or Bhutan, either an Indian visa along with foreign passport or a Long-Term Visa to India along with currently valid or expired foreign passport; or
- (C) Any one of the following documents, having the photograph of the beneficiary to evidence his relationship with the parent or legal guardian, namely:—
- (i) Ration card;
 - (ii) Caste certificate or domicile certificate, issued by a Gazetted officer who is an Executive Magistrate or a revenue officer of the State Government, not below the rank of Tahsildar;
 - (iii) Medical or insurance identity card issued by a government entity or public sector enterprise to a retired or serving public servant or his family member;
 - (iv) Indian passport;
 - (v) Certificate or statement of marks of matriculation or 10th class or higher secondary or 12th class, issued by a recognised board of school education;
 - (vi) In respect of a child in need of care and protection or a child in conflict with law, who is housed by Child Care Institution registered as such with the State Government concerned under the rules made by it under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (No. 2 of 2016), certificate specifying his date of birth issued by the person-in-charge, superintendent, child welfare officer or probation officer of such institution; or
 - (vii) In respect of a foreign national,—
 - (a) if he is an Overseas Citizen of India Cardholder, Overseas Citizen of India Card;
 - (b) if he is a Tibetan refugee, registration certificate issued by a Foreigners Regional Registration Office;
 - (c) if he is a national of Nepal or Bhutan, passport of Nepal or Bhutan;
 - (d) if he is other than a Overseas Citizen of India Cardholder, Tibetan refugee or a national of Nepal or Bhutan, either an Indian visa along with foreign passport or a Long Term Visa to India along with currently valid or expired foreign passport; or
 - (Viii) In respect of a beneficiary who has a legal guardian, adoption order or other document to evidence legal guardianship, which is issued by a court of law or Competent Authority under the Guardians and Wards Act, 1890 (No. 8 of 1890), the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (No. 2 of 2016), the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 (No. 44 of 1999) or the Rights of Persons with Disabilities Act,

2016 (No. 49 of 2016) and the applicable rules and regulations made under the said Acts; or

- (ix) Any other document as the said General Administration Department may specify. (Annexure-I)

For beneficiaries aged 18 years or more to whom an Aadhaar number has not been assigned:

- (A) The acknowledgement of the beneficiary having undergone the process of enrolment, provided by the operator at the enrolment centre, containing the Enrolment ID; and
- (B) Any one of the following documents, having the beneficiary's photograph, namely:—
- (i) Elector's Photo Identity Card issued by the Election Commission of India;
 - (ii) Ration card;
 - (iii) Caste certificate or domicile certificate, issued by a Gazetted officer who is an Executive Magistrate or a revenue officer of the State Government, not below the rank of Tahsildar;
 - (iv) Medical or insurance identity card issued by a government entity or public sector enterprise to a retired or serving public servant or his family member;
 - (v) Indian passport;
 - (vi) Certificate or statement of marks of matriculation or 10th class or higher secondary or 12th class, issued by a recognised board of school education;
 - (vii) Identity card or other identity document issued to serving or retired public servant by a government entity or a public sector enterprise;
 - (viii) Disability certificate issued by notified medical authority under Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, or Unique Disability Identification (UDID) card issued by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Government of India;
 - (ix) Driving licence issued in India;
 - (x) In respect of a child in need of care and protection or a child in conflict with law, who is housed by Child Care Institution registered as such with the State Government concerned under the rules made by it under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (No. 2 of 2016), certificate specifying his date of birth issued by the person-in-charge, superintendent, child welfare officer or probation officer of such institution; or
 - (xi) In respect of a foreign national,—
 - (a) if he is an Overseas Citizen of India Cardholder, Overseas Citizen of India Card;
 - (b) if he is a Tibetan refugee, registration certificate issued by a Foreigners Regional Registration Office;
 - (c) if he is a national of Nepal or Bhutan, passport of Nepal or Bhutan;
 - (d) if he is other than a Overseas Citizen of India Cardholder, Tibetan refugee or a national of Nepal or Bhutan, either an Indian visa along with foreign passport or a Long Term Visa to India along with currently valid or expired foreign passport; or
 - (xii) In respect of a beneficiary who has a legal guardian, adoption order or other document to evidence legal guardianship, which is issued by a court of law or Competent Authority under the Guardians and Wards Act, 1890 (No. 8 of 1890), the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (No. 2 of 2016), the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 (No. 44 of 1999) or the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (No. 49 of 2016) and the applicable rules and regulations made under the said Acts; or

- (xiii) Any other document as the said General Administration Department may specify: (Annexure I)

(4) An officer designated by the General Administration Department in this behalf shall check in respect of the documents presented or the information evidencing the contents thereof under clause (3),—

- (A) the status of the enrolment request by submitting the Enrolment ID on myAadhaar portal (<https://myaadhaar.uidai.gov.in/portal>) to confirm that the Enrolment ID is valid and that the enrolment request does not stand rejected; and
 - (B) the other documents, and for this purpose, may take the assistance of and share the information presented with any government entity or an authority that deals with the preparation or maintenance of the information contained in such documents.
2. In order to enable beneficiaries to avail of the said benefits conveniently, the Ministry shall make all necessary steps to ensure wide publicity through media to make the beneficiaries aware of the requirement of Aadhaar number under the said scheme.
 3. Where the authentication of the Aadhaar number of a beneficiary done through any of the biometric-based modes of authentication (namely, facial image, fingerprints or iris scan based authentication) fails due to any reason, such as poor quality of biometric information, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:—
 - (A) In case any particular biometric-based mode of authentication is not successful, any other mode of biometric-based authentication or one-time pin (OTP) based authentication shall, wherever feasible and admissible, be offered;
 - (B) In cases where biometric-based or OTP-based modes of authentication are not possible, benefits under the said scheme may, after establishing the genuineness of the Aadhaar number by doing offline verification of the digital signature certificate of UIDAI on the Aadhaar Secure Quick Response (QR) Code or the Aadhaar Paperless Offline e-KYC document, as the case may be, be given on the basis of any of the following:
 - (i) An Aadhaar Secure Quick Response (QR) Code containing Aadhaar card, Aadhaar letter (i.e., the letter issued to an Aadhaar number holder on generation of his Aadhaar number) or e-Aadhaar (i.e., the password-protected electronic copy of Aadhaar letter downloadable from the website of UIDAI or accessible using its mAadhaar app), after its genuineness is established through offline verification by scanning the QR code using the Aadhaar QR Scanner or mAadhaar apps.
 - (ii) Aadhaar Paperless Offline e-KYC document (downloadable from the website of UIDAI or accessible using its mAadhaar app), after its genuineness is established through offline verification of the digital signature certificate of UIDAI on the document through the application developed by the Ministry or Department or scheme implementing agency concerned for this purpose, in accordance with the details given in this regard on the website of UIDAI.
 4. Notwithstanding anything contained hereinabove,—
 - (A) benefit under the said scheme shall not be denied to a child—
 - (i) in case of failure to establish his identity by undergoing authentication or to furnish proof of possession of Aadhaar number; or
 - (ii) in case of production of an application for enrolment where he has not been assigned an Aadhaar number; and
 - (B) benefit under the said scheme shall be given to such a child by verifying his identity and establishing his relationship with his parent or legal guardian in the manner specified in the proviso to clause (3) of paragraph 1; and
 - (C) where benefit is given under clause (b), a record shall be maintained in respect of the same, which shall be reviewed and audited periodically by the General Administration Department.
 5. In order to ensure that bona fide beneficiaries who are aged 18 years or more are not deprived of the benefit due to them under the said scheme, the General Administration Department shall follow the exception handling mechanism specified in the Office Memorandum no. D-26011/04/2017-DBT, dated

the 19th December, 2017 of the Direct Benefit Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India (available on <https://dbtbharat.gov.in>).

6. This notification shall be effective from the date of its publication in the Official Gazette.

The Chief Minister may relax the said rules and approve the grant under the relevant scheme.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
AVINASH CHAMPAWAT, Secretary.

Annexure I

- Birth certificate
-